

कनाडा की हृदय-प्रशांत रणनीति

प्रलम्बिस के लयि:

प्रारंभिक प्रगतव्यापार समझौता (EPTA), व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) ।

मेन्स के लयि:

भारत-कनाडा संबंघ, भारत-कनाडा संबंघों में बाधाएँ, भारत के हतियों पर कनाडा की हृदय-प्रशांत रणनीतिक महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और कनाडा ने मार्च में नई दलिली में होने वाली **G20** वदलश मंत्रयियों की बैठक से पहले एक द्वपिक्षीय बैठक आयोजतल की जसल "भारत-कनाडा सामरकल वार्ता" के रूप में जाना जाता है ।

- भारत ने मुक्त, खुले और समावेशी हृदय-प्रशांत के साझा दृषटकलण को देखते हुए कनाडा की हृदय-प्रशांत रणनीतिक घोषणा का स्वागत कयल ।



//

प्रमुख बढल

- इन मंत्रयियों ने आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करने, सुरक्षा सहयोग बढाने, प्रवास और गतशीलता को सुवधलजनक बनाने के साथ ही लोगों से लोगों के

बीच संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की।

- कनाडाई वदेश मंत्री ने भारत को हदि-प्रशांत में कनाडा हेतु एक महत्त्वपूर्ण भागीदार करार दिया, जिसके बदले में कनाडा महत्त्वपूर्ण खनिजों का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता, हरति संक्रमण में एक मज़बूत भागीदार और प्रमुख नविशक हो सकता है।

बैठक का महत्त्व:

- वर्ष 2020 और 2022 के बीच ठहराव के बाद कनाडा के वदेश मंत्री की यात्रा से भारत-कनाडा संबंधों में स्थायित्व की उम्मीद है।
 - हालाँकि कई मुद्दों के कारण संबंधों में रुकावट आई थी, जिसमें खालसितानी समूहों द्वारा कनाडा में भारतीय मूल के लोगों और प्रतिष्ठानों पर हमले, भारत के किसानों के वरोध को लेकर कनाडा की टपिपणी एवं प्रतिक्रिया के चलते भारत द्वारा राजनयिक वार्ता को रद्द करना शामिल है।
 - भारत ने वर्ष 2022 में कनाडा द्वारा खालसितानी अलगाववादी "जनमत संग्रह" की अनुमति देने पर आपत्तजिताई, साथ ही कनाडा में घृणा अपराधों के खिलाफ चेतावनी के साथ आगाह किया।
- कनाडाई नविश को प्रोत्साहित करने के अलावा दोनों देश 'व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA)' की दिशा में 'प्रारंभिक प्रगत व्यापार समझौते (Early Progress Trade Agreement- EPTA)' को पहले कदम के रूप में देख रहे हैं।
- कनाडा में खालसितानी गतिविधियों, जसिने कनाडा और भारत के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बनाया, के मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया।
- जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, इसका सामरिक महत्त्व भी बढ़ता जाएगा, जसिसे कनाडा और भारत को अपने संबंधों को सशक्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
- दोनों देश चीन को संदेह की नज़र से देखते हैं और व्यापार संबंधों का वसितार, आपूर्ति शृंखला सुनम्यता में सुधार करने और अपने देशों में लोगों के अधिक-से-अधिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

कनाडा की हदि-प्रशांत नीति:

- परिचय:
 - कनाडा ने चार क्षेत्रों: चीन, भारत, उत्तरी प्रशांत (जापान एवं कोरिया) और आसियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई हदि-प्रशांत रणनीति जारी की है।
 - कनाडा में बड़ी संख्या में प्रवासी हदि-प्रशांत मूल के हैं। इसमें 5 में से 1 कनाडाई का इस क्षेत्र से पारिवारिक संबंध है और कनाडा में पढ़ने के लिये आए 60% अंतरराष्ट्रीय छात्र हदि-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित हैं।
 - लोकतंत्र और बहुलवाद की भारत की साझी वरिसत के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए मानवाधिकारों एवं कानूनों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के लिये चीन के खतरों के संबंध में यह रणनीति महत्त्वपूर्ण है।
 - हालाँकि कनाडा अपने मुख्य नरियात गंतव्य के रूप में चीन पर नरिभरता को भी स्वीकार करता है और जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चीन के साथ सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार करता है।
- वसितपोषण:
 - कनाडा की रणनीति में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, सैन्य उपस्थिति में वृद्धि और क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासों में वसितारित भागीदारी सहित पाँच वर्षों में 1.7 बिलियन डॉलर की वसितपोषण प्रतिबद्धता शामिल है।
- उद्देश्य:
 - शांति, सुनम्यता और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
 - व्यापार, नविश और आपूर्ति शृंखला के सुनम्यता का वसितार करना।
 - लोगों में नविश करना और उन्हें एकजुट करना।
 - एक स्थायी और हरति भवष्य का नरिमाण करना।
 - हदि-प्रशांत के लिये एक सक्रिय भागीदार बनना।

भारत-कनाडा संबंध:

- राजनीतिक:
 - भारत और कनाडा की संसदीय संरचना और प्रक्रिया कई मामलों में समान है। अक्टूबर 2019 में हुए आम चुनाव के बाद हाउस ऑफ कॉमन के सांसद राज सैनी को कनाडा-भारत संसदीय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - भारत में कनाडा का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा किया जाता है।
 - कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व ओटावा में एक उच्चायोग और टोरंटो तथा वैकूबर में वाणजिय दूतावासों द्वारा किया जाता है।
- आर्थिक:
 - वर्ष 2020 में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारत वर्ष 2021 में कनाडा का 14वाँ सबसे बड़ा नरियात बाज़ार और कुल मिलाकर 13वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
 - कनाडा की 400 से अधिक कंपनियों की भारत में उपस्थिति है तथा 1,000 से अधिक कंपनियों सक्रिय रूप से भारतीय बाज़ार में कारोबार कर रही हैं।
 - कनाडा में भारतीय कंपनियों सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, इस्पात, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
 - कनाडा को होने वाले भारत के नरियात में फार्मा, लौह एवं इस्पात, रसायन, रत्न एवं गहने, परमाणु रिएक्टर तथा बॉयलर शामिल हैं।
 - कनाडा के पास यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज और जल विद्युत, खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा में उन्नत

प्रौद्योगिकियों के दुनिया के सबसे बड़े संसाधन हैं।

■ विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

- प्राथमिक फोकस **औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास (R&D)** को बढ़ावा देने और नए **बौद्धिक संपदा (IP)** प्रक्रियाओं, प्रोटोटाइप या उत्पादों के विकास पर रहा है।
- **IC-IMPACTS कार्यक्रम** के तहत **जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वास्थ्य देखभाल, कृषि-बायोटेक और अपशिष्ट प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं** को लागू करता है।
 - **IC-IMPACTS** (भारत-कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सीलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी) **पहला और एकमात्र, कनाडा-इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** है।
- पृथ्वी विज्ञान विभाग और ध्रुवीय कनाडा ने **शीत जलवायु (आर्कटिक) अध्ययन पर ज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आदान-प्रदान** के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है।

■ अंतरिक्ष:

- **इसरो (ISRO)** और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने **बाह्य अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोग के क्षेत्र में समझौता** ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- ISRO की वाणिज्यिक शाखा **एंटरकिस** की सहायता से कनाडा के कई नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है।
- इसरो ने **वर्ष 2018 में लॉन्च किये गए अपने 100वें सैटेलाइट पीएसएलवी में श्रीहरिकोटा से कनाडा का पहला LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) सैटेलाइट भी लॉन्च** किया।

■ रक्षा क्षेत्र:

- भारत और कनाडा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विशेष रूप से **संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल और जी-20 के माध्यम से घनिष्ठ सहयोग** करते हैं।
- वर्ष 2015 में **डीआरडीओ और कनाडा की रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद** के बीच सहयोग पर एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये गए।
- **वर्ष 2018 में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये भारत और कनाडा के बीच** सहयोग की रूपरेखा के साथ सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाया गया।
- विशेष रूप से **काउंटर टेररिज्म** पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) के माध्यम से **आतंकवाद के मुद्दों पर पर्याप्त भागीदारी** रही है।

कनाडा के बारे में मुख्य तथ्य:

- क्षेत्रफल के हिसाब से (रूस के बाद) कनाडा **वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा देश** है, जिसका **उत्तरी अमेरिका महाद्वीप** के लगभग 2/5 हिस्से पर नियंत्रण है।
- कनाडा में **संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र** है।
 - संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि ब्रिटिश सम्राट राज्य का प्रमुख होता है लेकिन उसकी भूमिका मुख्य रूप से **प्रतीकात्मक और औपचारिक** होती है, जबकि देश का वास्तविक शासन **नरिवाचति प्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों** द्वारा किया जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा को मुख्य रूप से **49वें पैरेलल नार्थ** द्वारा परिभाषित किया गया है।
- कनाडा में **ग्रेट बयोर झील, ग्रेट स्लेव झील, वनिपिग झील** और USA सीमा पर 5 महान झीलों सहित कई झीलें हैं: **सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो**।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस देश के पास है? (2009)

- (a) ऑस्ट्रेलिया
- (b) कनाडा
- (c) रूसी संघ
- (d) संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- OECD-NEA (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन- परमाणु ऊर्जा एजेंसी)/IAEA (अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) के नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, विश्व परमाणु संघ में सम्मिलित देशों के पास यूरेनियम की उपलब्धता इस प्रकार है- ऑस्ट्रेलिया (30%), कजाखस्तान (14%), कनाडा (8%), रूस (8%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (1%)। **अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।**

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

